



84

न्यायालय मान० राजस्व मण्डल, म० प्र० ग्वालियर
क्र० ५० एक-निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/2459

- 1- हबीब खां पुत्र खुशाल खाँ
- 2- माधव रजक पुत्र गवूले रजक
- 3- दयाराम रजक पुत्र बबूले रजक
तीनों ग्राम खरौं तहसील लिधौरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
विरुद्ध

---आवेदकगण

- 1- राजबहादुर पुत्र घनश्यामदास राय
ग्राम खरौं तहसील लिधौरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

- 2- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

---अनावेदकगण

सी.ए. रायक, म० प्र०
दि. 17-4-18 को
प्रतिकर्षक हेतु
दि. 27-4-18 नियत।

कलक ऑफ प्रोट
राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50, म० प्र० भू राजस्व संहिता, 1959
- श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त स्यावनी तहसील लिधौरा जिला
टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 5 अ12/2016-17 में पारित
आदेश दि. 25-11-16 के विरुद्ध)

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

महोदय

यह कि मूल विवाद ग्राम खरौं स्थित भूमि सर्वे क्रमांक
1284/6 का है क्योंकि इस भूमि के अंश भाग पर लोक निर्माण विभाग
की पक्की सड़क है एवं इसी भूमि के अंश भाग पर आवेदकगण के
पीढ़ियों से मकान बने हुये है, जिन्हें अनावेदक क्रमांक-1 स्वयं स्वीकार
कर रहा है।

यह कि अनावेदक क्रमांक 1 ने तहसील न्यायालय में ग्राम खरौं
स्थित भूमि स० क्र० 1284/1, 1284/2/2, के सीमांकन का
आवेदन दिया। हलका पटवारी ने आवेदकगण को एवं लोक निर्माण
विभाग को सूचना दिये बिना कब सीमांकन कर दिया, आवेदकगण को
पता नहीं चला एवं लोक निर्माण विभाग की सड़क तथा आवेदकगण के
पुस्तैनी मकानों को अनावेदक क्र-1 की भूमि में होना हलका पटवारी ने
बता दिया, जिसके कारण पटवारी द्वारा किये गये सीमांकन दिनांक
25-11-16 को राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 25-11-16 से
अंतिमता प्रदान नहीं की, फिर भी सीमांकन के अंतिम हुये बिना ही

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

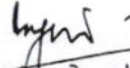
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/2459

हबीव खां विरूद्ध राजबहादुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-02-2019 11-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक स्यावनी तहसील लिधौरा के प्रकरण क्रमांक 05/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 25-11-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी लिधौरा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी लिधौरा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये ।	

3


(आर.के. जैन) 11/02/2019
सदस्य